प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 11.07.2017 को संपन्न विभागीय पदाधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 11.07.2017 को विभागीय पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी उपस्थित हुए।

2. प्रबंध निदेशक, बुडको को निर्देश दिया गया कि सोनपुर जलापूर्ति योजना में बोरिंग किये जाने हेतु प्राक्कलन तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराया जाय। विभाग द्वारा पेयजल निश्चय योजना के तहत सोनपुर जलापूर्ति योजना में बोरिंग के अधिष्ठापन हेतु राशि विमुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। हाऊस टू हाऊस कनेक्शन का कार्य सोनपुर नगर निकाय द्वारा किया जाएगा।

(अनुपालन :– प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रशाखा पदाधिकारी–2)

3. विभाग में सचिवालय सहायक के रिक्त पदों पर बिहार सचिवालय सेवा के 'सहायक' पद से सेवानिवृत्त कर्मियों की संविदा पर नियोजन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०–10000 दिनांक 10.07.2015 के आलोक में इस सप्ताह के अंत तक विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–1)

4. विभाग में ई०–ऑफिस चालू करने के संबंध में आई०टी० मैनेजर द्वारा बताया गया कि इस हेतु प्रशाखा–11/अभियंत्रण कोषांग में कम्प्यूटर अधिष्ठापित कर दी गयी है। इनमें अभी इंटरनेट उपलब्ध नहीं कराया गया है।

इस कार्य में धीमी प्रगति के कारण कड़ी चिंता व्यक्त की गयी। पिछले कई बैठकों से इन्हें ई०–ऑफिस शीघ्र चालू करने हेतु निदेशित किया जाता रहा है, लेकिन अभी तक यह कार्य नहीं हो पाया है। निर्देश दिया गया कि आज ही तत्काल अभियंत्रण कोषांग/प्रशाखा–11 की संचिकाएं ई०–ऑफिस के माध्यम से चालू कराया जाय।

अधोहस्ताक्षरी कोषांग में अभियंत्रण कोषांग/प्रशाखा–11 की संचिकाएं आज से ई०–ऑफिस के माध्यम से ही प्राप्त की जाएगी।

(अनुपालन :– आई०टी० मैनेजर)

5. विभाग द्वारा 02 सहायक अभियंता श्री विकास कुमार एवं श्री सुबोध कुमार का अन्यत्र स्थानांतरण तथा श्री उमाकांत ठाकुर, अधीक्षण अभियंता की सेवा वापसी की गयी है। ये सभी अभियंता विभिन्न जिलों के नोडल पदाधिकारी के रूप में भी नामित थे तथा श्री विकास कुमार ई०–कम्प्लायंस डैशबोर्ड के नोडल पदाधिकारी भी थे।

निर्देश दिया गया कि इनके स्थान पर विभाग में नवपदस्थापित अभियंताओं को इनसे संबंधित जिलों का नोडल पदाधिकारी नामित किया जाय तथा ई०–कम्प्लायंस डैशबोर्ड का नोडल पदाधिकारी भी किन्हीं अभियंता/पदाधिकारी को नामित किया जाय।

(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–1)

6. विभागीय संवर्ग के कर्मियों यथा समूह 'घ' एवं निम्नवर्गीय लिपिक की प्रोन्नति हेतु वरीयता सूची प्रकाशित की जाय। विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक माह अगस्त में निर्धारित की जाय। विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक के पूर्व तक संबंधित सभी कर्मियों की वरीयता सूची/सेवा सम्पुष्टि/वार्षिक चारित्री आदि प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली जाय। जिन कर्मियों का ACP/MACP लंबित है, उन्हें ACP/MACP देने हेतु प्रस्ताव संचिका में एक सप्ताह के अंदर उपस्थापित किया जाय।

प्रशाखा पदाधिकारी–1 द्वारा बताया गया कि ACP/MACP हेतु विभाग में लगभग 20 कर्मी हैं, जिनकी सेवापुस्त अद्यतन करने की कार्रवाई की जा रही है। निर्देश दिया गया कि सभी प्रक्रियाएं शीघ्र पूर्ण करके संचिका उपस्थापित की जाय।

(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं 11)

7. श्री सुरेश तिवारी, अधीक्षण अभियंता वर्तमान में हर घर नल जल योजना के नोडल पदाधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त इनके पास वर्तमान में काफी कार्य हैं। पथ निर्माण विभाग से कई कार्यपालक अभियंताओं की सेवा विभाग में प्राप्त हुई है। इनमें से किन्हीं 01 कार्यपालक अभियंता को नल जल योजना के नोडल पदाधिकारी का दायित्व दिया जाय।

(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–1)

8. Ease of Doing Buisiness, 14th FC Reforms, 5th SFC Reforms एवं AMRUT Reforms अंतर्गत प्रत्येक बिन्दु/मुद्दे पर प्रत्येक सप्ताह संचिका में प्रस्ताव अनिवार्य रूप से उपस्थापित करने का निर्देश पूर्व से दिया जाता रहा है, लेकिन इसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है।

   निर्देश दिया गया कि 14th FC Reforms एवं 5th SFC Reforms के सभी बिन्दुओं को समेकित करके प्रस्ताव एक ही संचिका में उपस्थापित किया जाय।

(अनुपालन :– श्री अरविन्द कुमार, का०अभि०/TCPO/प्रशाखा पदाधिकारी–2)

9. कई संचिकाओं में यह देखा जा रहा है कि विभागीय पदाधिकारियों द्वारा संचिका में प्रस्ताव निर्णय लेने हेतु उपस्थापित किया जा रहा है। इस संबंध में सभी योजना के नोडल पदाधिकारी एवं प्रशाखा के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि संचिकाओं में अपना स्पष्ट मंतव्य/प्रस्ताव अंकित करेंगे।

(अनुपालन :– सभी विभागीय पदाधिकारी)

10. मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत सभी नगर पंचायतों को वर्ष 2017–18 के लिए राशि आवंटित कर दी गयी है, लेकिन नगर परिषदों को अभी राशि आवंटित नहीं हो पायी है। निर्देश दिया गया कि इस योजनांतर्गत सभी नगर परिषदों (AMRUT योजना वाले नगर निकाय को छोड़कर) को राशि आवंटित करने की कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–2)

11. नाली–गली निश्चय योजना एवं पेयजल निश्चय योजना के नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे इस योजनांतर्गत सभी योजनाओं में नगर निकायों द्वारा प्रत्येक वार्ड की निविदा शीघ्र प्रकाशित करने हेतु सभी नगर निकायों के साथ दूरभाष के माध्यम से समन्वय सुनिश्चित करेंगे एवं जिन नगर निकायों द्वारा निविदा प्रक्रिया करने में यदि कहीं कोई समस्या है तो उसकी जानकारी प्राप्त करके समेकित प्रतिवेदन तैयार कर एक सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएंगे।

(अनुपालन :– श्री सुरेश तिवारी, अधी०अभि०/श्री सोमेश कुमार सिंह, का०अभि०)

12. जिले के सभी नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने जिले के नगर निकायों के साथ मुख्यमंत्री निश्चय योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने एवं निविदा प्रक्रिया के शीघ्र निष्पादन हेतु दूरभाष पर प्रतिदिन समन्वय सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन :– जिले के सभी नोडल पदाधिकारी)

13. बिहार विकास मिशन के कार्य से संबंधित नोडल पदाधिकारी श्रीमती इन्दु कुमारी, वि०का०पदा० को निर्देश दिया गया कि वे प्रत्येक गुरूवार को श्री जयप्रकाश मंडल, विशेष सचिव के स्तर पर निर्धारित बिहार विकाश मिशन से संबंधित विषयों की समीक्षा बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित करेंगी एवं बैठक की कार्यवाही अनिवार्य रूप निर्गत की जाएगी।

(अनुपालन :– श्रीमती इन्दु कुमारी, OSD)

14. मुख्यमंत्री नाली–गली योजनांतर्गत पिछले वर्ष नगर निकायों को आवंटित की गयी प्रथम किस्त की राशि का शत–प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाय। जिन नगर निकायों द्वारा शत–प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग में प्राप्त हो जाता है, उन्हें इस वर्ष राशि आवंटित करने की कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–2)

15. अन्य राज्यों के Advertisement rules का अध्ययन करके राज्य के नगर निकायों के लिए Advertisement rules तैयार करने हेतु प्रशाखा पदाधिकारी–5 द्वारा शीघ्र अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन :– निदेशक, नगरपालिका प्रशासन)

16. स्वच्छता एक्शन प्लान तैयार करने हेतु भारत सरकार से संभवतः दिशानिर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में विभाग स्तर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पायी है।

निर्देश दिया गया कि भारत सरकार के वेबसाईट एवं अन्य राज्यों द्वारा तैयार किए गए एक्शन प्लान का अध्ययन करके उसके आधार पर स्वच्छता एक्शन प्लान तैयार करने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र की जाय। **(अनुपालन :– श्रीमती इन्दु कुमारी, वि०का०प०)**

17. ई–म्युनिस्पिलिटी अंतर्गत ABM knowledgeware कंपनी द्वारा 58 नगर निकायों में कार्य किया जा रहा है, जिसके कार्य का प्रतिवेदन कई नगर निकायों द्वारा विभाग में भेजे गए हैं। आई०टी० मैनेजर को निर्देश दिया गया कि नगर निकायों से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा करके एक समेकित प्रतिवेदन तैयार कर प्रशाखा पदाधिकारी–3 को उपलब्ध करा दिया जाय। प्रशाखा पदाधिकारी–4 द्वारा यह प्रतिवेदन संचिका में इस सप्ताह के अंत तक अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित की जाएगी।

(अनुपालन :– श्री अमितेष, आई०टी० मैनेजर/प्र०पदा०–3)

18. शहरी स्थानीय निकायों के लिए water user charges के संबंध में मार्गनिर्देश तैयार किया जाय। इस हेतु पंचायती राज विभाग एवं अन्य राज्यों की policy का अध्ययन करके राज्य के लिए policy तैयार किया जाय। पेयजल योजना के रखरखाव एवं देखरेख हेतु वार्ड स्तर पर एक वार्ड कमेटी गठन करने हेतु नगर निकायों को दिशानिर्देश निर्गत किया जाय। **(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–2)**

19. पटना मेट्रो रेल के SPV के गठन के संबंध में प्रशाखा पदाधिकारी–3 द्वारा आश्वासन दिया गया कि इसकी संचिका में प्रस्ताव आज ही उपस्थापित कर दी जाएगी। **(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–3)**

20. राज्य के लिए Urban Transport Policy तैयार किया जाना है। निर्देश दिया गया कि Urban Transport Policy तैयार हेतु National Institute of Urban Transportation से MOU करने की कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–3)

21. Urban Transport Policy कार्य हेतु श्री प्रेमनाथ, कार्यपालक अभियंता को नोडल पदाधिकारी नामित करने हेतु आदेश निर्गत किया जाय। **(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–1)**

22. प्रशाखा पदाधिकारी–4 को निर्देश दिया गया कि बुडा द्वारा HFA, SBM आदि योजनाओं में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार कार्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–4)

23. स्वच्छता अनुदान मद में वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में नगर निकायों को आवंटित की गयी राशि में जिन नगर निकायों द्वारा 60 प्रतिशत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग में समर्पित कर दिया गया है, उन नगर निकायों को इस मद में इस वर्ष की राशि आवंटित करने की कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन :– प्रशाखा पदाधिकारी–2)

24. सी०ए०जी० रिपोर्ट, लोक लेखा समिति का ऑडिट रिपोर्ट, Compliance report, नगर निकायों का बजट आदि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की जाय। प्रशाखा पदाधिकारी–7 द्वारा Compliance report श्री अमितेष, आई०टी० मैनेजर को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाएगी एवं वे इस हेतु सभी संबंधितों के साथ समन्वय सुनिश्चित करेंगे।

प्रशाखा पदाधिकारी–7 को यह भी निर्देश दिया गया कि CAG का Compliance report यदि ससमय नगर निकायों/एजेंसियों से प्राप्त नहीं होता है तो उसे उस जिले के लिए नामित नोडल पदाधिकारी को समन्वय करके प्राप्त करने हेतु उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन :–प्रशाखा पदा०–7 एवं आई०टी० मैनेजर)

25. प्रशाखावार/कोषांगवार संबंधी अन्य महत्वपूर्ण कार्यो की विवरणी अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है। इनमें वैसे मुद्दे, जो अभी तक लंबित हैं, उसकी सूची तैयार कर ली जाय एवं अगली बैठक में विमर्श हेतु उपस्थापित किया जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

12/7/2017

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 4598 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 12.7.17

प्रतिलिपि :– सभी विभागीय पदाधिकारी/जिले के सभी नोडल पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/Team Leader, PMC (NULM)/SPMG कोषांग/Team Leader, MIS/अभियंत्रण कोषांग/TCPO/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/7/2017

प्रधान सचिव

<u>अनुलग्नक</u>–1

➢ **प्रशाखा–01 :–**

1. अधीनस्थ कार्यालय यथा नगरपालिका निदेशालय, बुडको, बुडा, बिहार राज्य जल पर्षद एवं बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड के रिक्तियों को भरने हेतु कदम उठाना।
2. विभाग के सहायकों एवं अन्य सभी कर्मियों के बीच कार्यों का स्पष्ट विभाजन करना।
3. ई० ऑफिस लागू करना।

➢ **प्रशाखा–02 :–**

1. <u>सभी घरों में पाईप जलापूर्ति की व्यवस्था</u> :–

- राज्य के सभी घरों में पाईप जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराना, सरकार के 7 निश्चयों में से है। तदनुसार इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शहरी क्षेत्र के लिए कार्य योजना तैयार की जाय। जो योजनाएं कार्यान्वित हैं, उन्हें गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए शीघ्र पूर्ण किया जाय।
- सामान्य परिस्थिति में भविष्य में ली जाने वाली योजनाओं में जलमीनार आधारित पेय जलापूर्ति योजना के स्थान पर समीक्षा कर Direct Supply आधारित योजनाएं लेने पर विचार किया जाय। छोटे–छोटे Zones का गठन किया जा सकता है।
- शहरी स्थानीय निकायों/बिहार राज्य जल पर्षद की क्षमता में वृद्धि की जाय ताकि पेय जलापूर्ति योजनाओं का उचित संधारण सुनिश्चित हो सके।
- शहरी स्थानीय निकाय, सतत् संधारण के दृष्टिकोण से निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप उपभोक्ता शुल्क वसूल करने की कार्रवाई करें।
- इस महत्वपूर्ण कार्य हेतु राशि की बड़ी आवश्यकता के मद्देनजर विभिन्न स्रोतों से निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किया जाय।
- नगर निकायों के सरकार के 7 निश्चय की प्राथमिकता के अनुरूप योजना चयनित करने के लिए उचित मार्गदर्शन दिया जाए।
- शहरी स्थानीय निकायों की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने हेतु एक प्रोत्साहन योजना बनायी जाय, जिसमें सरकार के 7 निश्चय की प्राथमिकता के अनुरूप योजना लेने के लिए शहरी स्थानीय निकाय को प्रोत्साहित किया जाए। इसमें अंतर वार्ड महत्व की योजनाओं में राज्य सरकार का प्रोत्साहन एक वार्ड तक सीमित योजनाओं की तुलना में अधिक रखी जाय।
- बिहार राज्य जल पर्षद् का ढाँचा, क्षेत्र स्तर तक विस्तारित किया जाय ताकि जलापूर्ति से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन एवं संधारण, नगर निकायों से समन्वय करके प्रभावी तरीके से किया जा सके।
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बनायी गयी जलापूर्ति योजनाओं के उचित संधारण विभाग से ही करने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाय।

- स्वच्छता अनुदान घटक का कड़ा अनुश्रवण किया जाय ताकि सभी शहरों में डोर–टू–डोर कचरा उठाव हो सके। कचरे के भंडारण हेतु भूमि की व्यवस्था हो सके तथा कचरे की प्रोसेसिंग की व्यवस्था हो सके।
- पटना में बस स्टैण्ड का निर्माण शीघ्र आरंभ किया जाना चाहिए। इस हेतु HUDCO से ऋण के मामले में राज्य सरकार की गारंटी संबंधी विषय पर वित्त विभाग से शीघ्र समन्वय किया जाय। HUDCO से भिन्न, यदि कोई अन्य संस्था कम दर पर ऋण देती हो तो उसकी भी संभावना तलाशी जाय।

2. <u>स्ट्रीट लाईट</u> :–

- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्ट्रीट लाईट को बढ़ावा दिया जाय एवं संधारण की प्रभावी व्यवस्था की जाय। चरणबद्ध तरीके से प्रधान मुख्य सड़कों एवं मुख्य सड़कों को पहले आच्छादित किया जाय। पथ निर्माण विभाग एवं अन्य विभाग, जिनके द्वारा पथों का निर्माण शहरी क्षेत्रों में किया जाता है, वे आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाईट का प्रावधान करें। इस पर संबंधित विभागों से समन्वय किया जाय।

3. पार्क एवं हरियाली विस्तार :-

- नगर क्षेत्र में पड़ने वाले पार्कों के संधारण हेतु पर्यावरण एवं वन विभाग को सौंपने की कार्रवाई की जाय एवं राशि का प्रावधान किया जाय। इसके लिए आवश्यकतानुसार निदेश निर्गत किये जाए।
- अन्य शहरों में पार्कों के संधारण हेतु पार्क विकास एवं संधारण नीति बनाकर परिचालित की जाय।
- पार्क/हरियाली क्षेत्र के विस्तार हेतु प्रभावी कदम उठाया जाय।

4. सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020 :-

(i) बिहार के प्रत्येक शहर में मुहल्लों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक घर पक्की सड़क से जुड़े, इसके लिए सभी मुहल्लों में गलियों एवं नालियों का निर्माण किया जाएगा।

(ii) राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

(iii) सभी शहरी घरों में डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छता सहायता अनुदान कार्यक्रम लागू किया जाएगा। सभी शहरों में कचड़ा प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था लागू की जाएगी।

(iv) सभी नगरों में पार्क एवं जन–सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा।

➤ प्रशाखा–03 :-

1. केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य को मिलने वाले संसाधन समय पर मिले, इसके लिए भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय के साथ समुचित समन्वय सुनिश्चित करना।

2. जल निसरण :-

- इस बात पर चिन्ता व्यक्त की गयी कि विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा बनाये जाने वाले ड्रेनेज का प्रभावी उपयोग नहीं हो पाता है। अतः समस्या को दूर करने के लिए शहरों का ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया जाय और उसीके तहत सभी कार्यान्वयन एजेंसी, योजनाओं का चयन एवं कार्यान्वयन करें।

3. शहरी परिवहन :-

- उत्तर बिहार एवं पश्चिम बिहार के क्षेत्रों से आने–जाने वाली बसों के लिए हाउसिंग बोर्ड, दीघा कॉलोनी में भी एक बस स्टैण्ड विकसित करने पर विचार किया जाय।
- नगर निगम शहरों का City Mobility Plan तैयार किया जाय।
- शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले पथांसों के लिए Urban Road Policy तैयार करके संबंधित विभागों से विचार–विमर्श किया जाय।

4. सबके लिए शौचालय :-

- हर घर में शौचालय की सुविधा भी सरकार के 7 निश्चयों में से है। तदनुसार इसके निर्धारित अवधि में प्राप्ति हेतु ठोस कार्य योजना बनाई जाए। कार्यान्वयन में खुलापन, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित हो।
- शहरी क्षेत्र के वैसे परिवार जो वर्त्तमान सूची में छूटे हुए है उनको सम्मलित करने की कार्रवाई की जाए।
- सामुदायिक शौचालयों का रखरखाव एक चुनौती होता है। इसे ध्यान में रखते हुए यथासंभव सामुदायिक शौचालयों की स्थापना तभी की जाए जब इसके संधारण की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो।
- वैसे घर, जहाँ शौचालय बनाने के लिए जगह उपलब्ध नहीं हो, उनके लिए नजदीक में समूह में शौचालय निर्माण कर, पारिवारिक आधार पर शौचालय आवंटित किया जाय।
- सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव में खुलापन एवं पारदर्शिता बरतते हुए, शहरी स्थानीय निकाय स्वयंसेवी संस्थाओं को संबद्ध करती है। इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शौचालयों का संधारण उचित तरीके से हो रहा है। सुलभ इंटरनेशनल जैसी ख्याति प्राप्त संस्थाओं को Nomination के आधार पर सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण एवं रखरखाव कार्य देने के बिन्दु पर गहन विचार–विमर्श करके प्रस्ताव गठित किया जाय।
- वैसी आबादी, जो अनाधिकृत रूप से बाँध आदि पर रह रहे हों, उनके लिए भी जमीन उपलब्ध कराते हुए, मल्टीस्टोरी भवन का निर्माण कराने की संभावना तलाशी जाय ताकि उनके लिए आवास एवं शौचालय की व्यवस्था एकसाथ हो सके।

5. सिवरेज की व्यवस्था :–

- भारत सरकार के स्तर पर लंबित मुद्दों के त्वरित निष्पादन के लिए प्रभावी समन्वय एवं पत्राचार सुनिश्चित किया जाय।
- कार्यान्वित योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लायी जाय। और उन्हें पूर्ण कराया जाए।
- नमामि गंगे योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक योजनाएं प्रेषित करके स्वीकृति प्राप्त की जाय।
- गंगा नदी के किनारे अवस्थित वे प्रमुख शहर, जिनके वित्त पोषण की व्यवस्था नहीं हो पायी है, वहाँ आवश्यकतानुसार राज्य योजना से सिवरेज के कार्य लिये जाएं यथा मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, फतुहा, बड़हिया, लखीसराय, बिहारशरीफ आदि। साथ ही भारत सरकार से भी लगातार मांग की जाती रहे।
- गंगा की सहायक नदियों पर अवस्थित शहरों पर भी STP एवं सिवरेज नेटवर्किंग के कार्य को समावेशित करने के बिन्दु पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।
- पटना शहर की सिवरेज परियोजना का गुणवत्तापूर्ण ससमय कार्यान्वयन हो, इसके लिए अत्यधिक विशेष अनुश्रवण की व्यवस्था की जाय।

6. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन :–

- पटना में कार्यान्वित हो रहे Waste to Energy प्रोजेक्ट का सघन अनुश्रवण करके तेजी से कार्यान्वयन कराया जाय। छोटे शहरों में Waste to Compost पर विचार किया जाए।

7. सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020 :–

(i) चरणबद्ध तरीके से सभी शहरों में सीवरेज एवं ड्रेनेज की योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाएगा।
(ii) राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
(iii) स्ट्रीट वेण्डरों की आजीविका की सुरक्षा हेतु शहरों में सुव्यवस्थित वेण्डिंग जोन स्थापित किए जाएंगे।

➢ **AMRUT Mission से संबंधित कार्य** :–

(i) AMRUT योजना के अंतर्गत जो योजनाएं ली जा रही हैं एवं SAAP में जो योजनाएं शामिल हैं, उसका डी०पी०आर० बनाकर, सक्षम स्तर पर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जाय।

➢ प्रशाखा–04 :–

1. सबके लिए आवास (शहरी) :–

- शहरी क्षेत्रों के आवास विहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए बहुमंजिले मकान बनाना उचित विकल्प है। तदनुसार भूमि की उपलब्धता के बिन्दु पर नीति/दिशानिर्देश बनाने के लिए मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक आयोजित करके निर्णय लेना।
- Affordable Housing Policy, Rental Housing Policy and Model Tenancy Act पर अग्रेत्तर कार्रवाई।

2. आवास योजना का MIS लागू करना।

3. भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित Technology Development Centre की स्थापना का प्रस्ताव भेजना।

4. सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020 :–

(i) स्ट्रीट वेण्डरों की आजीविका की सुरक्षा हेतु शहरों में सुव्यवस्थित वेण्डिंग जोन स्थापित किए जाएंगे।

- **NULM से संबंधित कार्य** :–

शहरी क्षेत्रों के सभी गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह के नेटवर्क में चरणबद्ध तरीके से समयसीमा के अंतर्गत आच्छादित किया जाय। गरीब महिलाओं के समूहों को Area Level Organization एवं City Level Federation के रूप में संगठित कराया जाय।

➢ प्रशाखा–05 :–

1. नगर निकायों के होल्डिंग टैक्स को पूरे राज्य में प्रभावी तरीके से लागू करना।
2. नगर निकायों का GIS Based Survey एवं Property Tax Survey के कार्य को कड़ा अनुश्रवण करके समय पर पूर्ण कराना।

3. नगर निकायों के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए सभी घटकों यथा मोबाईल टावर, ट्रेड लाईसेंस आदि सभी पर अलग–अलग संचिका खोलकर, मार्गनिर्देश जारी करना एवं अनुश्रवण करना।
4. प्रशाखा–5, नगरपालिका प्रशासन, निदेशालय के तौर पर तदर्थ रूप से कार्य करें, इसकी व्यवस्था करना।
5. नगर निकायों का गठन/पुनर्गठन :–
   - नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर शहरीकरण के दृष्टिकोण से उचित हो, वैसे नये नगर पंचायतों का गठन का प्रस्ताव लाया जाए।
   - बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में संशोधन प्रस्तावित किया जाय ताकि सभी गठित नगर निकायों के चुनाव एकसाथ होने की व्यवस्था का प्रावधान हो सके।
6. नगरीय प्रशासन :–
   - "मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय प्रोत्साहन योजना" शहरी स्थानीय निकायों में स्वस्थ प्रतियोगिता पैदा करेगी। इसे तत्काल लागू किया जाय।
   - शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार की अत्यधिक संभावना है। तदनुसार कमीशन आधारित मानव बल की व्यवस्था की जा सकती है। Online Tax Collection को प्रभावी बनाया जाय। सभी प्रकार के Fee/कर की प्रभावकारी वसूली सुनिश्चित की जाय।
   - नगर निकायों के 'लोक वित्त' प्रबंधन व्यवस्था को प्रभावकारी बनाने हेतु किये जा रहे प्रयासों यथा Double Entry Accounting System (DEAS), Online Tax Collection, E-Tendering, e-auction, Internal Audit आदि सभी कार्यों को सभी नगर निकायों में बढ़ावा दिया जाय।
   - शहरी स्थानीय निकायों में मानव बल की कमी के लिए नियमित नियुक्ति की जाय। संविदा/एच०आर० एजेंसी आधारित नियुक्ति की बजाए सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा, तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए लेने हेतु नीति बनायी जाय।
   - शहरी स्थानीय निकायों के मानव बल की आवश्यकता का पुनर्गठन कराया जाय।
   - पटना नगर निगम का पुनर्गठन, वर्तमान दायित्व के मद्देनजर किया जाय।
   - विकास कार्यों को गति देने के लिए "शहरी अभियंत्रण संगठन" स्थापित किया जाय। इसके लिए BUIDCO एवं जल परिषद के पुनगर्ठन पर विचार किया जाए।
   - Development Management Institute, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित की गयी संस्था है, उससे समन्वय करके, शहरी प्रशासन के मुद्दों पर कार्रवाई की जाय।
   - अतिक्रमण हटाने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया जाय।
7. सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020 :–
   (i) शहरी प्रशासनिक व्यवस्था को संवेदनशील, जनोन्मुखी, जिम्मेदार एवं पारदर्शी बनाने के दृष्टिकोण से शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त एवं आर्थिक रूप से स्वाबलंबी बनाने के प्रयास को गति प्रदान की जाएगी।

➢ **प्रशाखा–6 :–**

1. विधानमंडलीय मामलों में कड़ा अनुश्रवण करके, प्रतिदिन के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित कराना।

➢ **प्रशाखा–07 :–**

1. लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी०सी० विपत्रों का प्रभावी निष्पादन।
2. 14वें वित्त आयोग की Performance Grant की पात्रता हेतु नगर निकायों की चार्टर्ड एकाउंटेंट के द्वारा अंकेक्षण की व्यवस्था SPUR के माध्यम से कराना।
3. Doubel Entry Accounting System को Roll Out कराना।

➢ **प्रशाखा–8 :–**

1. लंबित CWJC/MJC का प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप प्रभावी निष्पादन जारी रखना।

➢ **प्रशाखा–9 :–**

1. RTI के मामलों पर सामयिक निष्पादन करके, प्रभारी पदाधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा एवं प्रधान सचिव के अवलोकन हेतु मासिक प्रतिवेदन तैयार करना।

➢ **प्रशाखा–10** :–

1. बिहार राज्य आवास बोर्ड की संसाधनों में वृद्धि करना।
2. दीघा पुनर्वास योजना को लागू करना।

- आरक्षण नीति में संशोधन, e-auction, Online Property Management एवं EPC Mode पर अधिक से अधिक फ्लैट बनाने का प्रयास किया जाय।
- बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा अपनी सम्पत्तियों का प्रभावी प्रबंधन किया जाय। लीज होल्ड से फ्री–होल्ड करने संबंधी सरकार के निर्णय को शीघ्र कार्यरूप दिया जाय। इसके लिए मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक कर आवश्यक अंतर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित किया जाय।
- बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा जो आवास बनाये जा रहे हैं, उन्हें माननीय MLA/MLC के लिए आवंटन करने पर विचार किया जाय।
- बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा बनाये गये मकानों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। दीघा में स्थित आवास बोर्ड की जमीन पर चहारदीवारी का निर्माण कराया जाय।

➢ **प्रशाखा–11** :–

1. **शहरों का सुनियोजित विकास** :–

- मुख्यमंत्री नगर विकास योजना को शहरीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए Re-design किया जाय एवं इसे सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत ली जाने वाली योजनाओं में प्राथमिकता दी जाय।
- सुनियोजित शहरीकरण हेतु Regulatory Frame Work बनाया जाय। मुख्य सचिव इसे अपने स्तर पर देखेंगे।
- नक्सा पारित करने के काम में तेजी लायी जाय। इसमें किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं हो। जनसाधारण को काई कठिनाई नहीं हो, ऐसी व्यवस्था की जाय। इस हेतु विभाग द्वारा विकसित की जा रही ऑनलाईन नक्सा प्रबंधन व्यवस्था को शीघ्र लागू किया जाय।
- "पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑथोरिटी" को शीघ्र कार्यरत किया जाय।
- पटना मास्टर प्लान, 2031 को विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए उपस्थापित किया जाय।
- 15 प्रमुख शहरों का "आयोजना क्षेत्र" घोषणा, आयोजना प्राधिकार का गठन एवं मास्टर प्लान का कार्य प्राथमिकता पर पूर्ण किया जाय।
- शहरों के आस–पास नई टाउनशिप विकसित हो, ऐसा प्रयास किया जाय।
- "नया पाटलिपुत्र" बसाने हेतु अग्रेत्तर योजना बनायी जाय।
- TCPO में सेवानिवृत्त कर्मियों की संभावित उपलब्धता नहीं होने के मद्देनजर खुले बाजार से योग्य एवं अनुभवी Professionals लिए जा सकते है।
- पटना राजधानी क्षेत्र में सभी विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों के मद्देनजर अंतर्विभागीय समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "Patna Capital Region Management Committee" गठित की जाय।
- पटना मेट्रो रेल परियोजना हेतु विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त की जाय। अग्रेत्तर कार्रवाई के लिए भारत सरकार को भेजा जाय।

2. **सुशासन के कार्यक्रम 2015–2020** :–

(i) शहरों के सुव्यवस्थित विकास के उद्देश्य से सभी जिला–मुख्यालय शहरों का दीर्घकालीन मास्टर प्लान तैयार कर लागू किया जाएगा।

3. TCPO कार्यालय का सुदृढ़ीकरण।

➢ **SPMG कोषांग से संबंधित कार्य** :–

(i) NGRBA के अंतर्गत स्वीकृत कार्यरत योजनाओं को गति देना।
(ii) NMCG के साथ प्रतिदिन समन्वय सुनिश्चित करना।